भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या-2666**
उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

## तमिलनाडु के समग्र शिक्षा अभियान के लिए निधि को रोकना

**†2666. श्री सु. वेंकटेशन:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत तमिलनाडु को मिलने वाली 2154 करोड़ रुपये की निधि रोक रखी है;
(ख) सरकार ने उपरोक्त निधि जारी करने को राज्य में एनईपी के कार्यान्वयन से क्यों जोड़ा है;
(ग) क्या एनईपी के हिस्से के रूप में हिंदी को लागू करना तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि में विकसित भाषाई विविधता को स्वीकार करने वाली भाषा नीति का उल्लंघन है;
(घ) क्या उपरोक्त को लागू करना संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन है जबकि शिक्षा समवर्ती सूची में है; और
(ङ.) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री जयन्त चौधरी)**

(क) और (ख): केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश के हर कोने में हर बच्चे को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) के परिवर्तनकारी लाभों तक पहुंच मिले। समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जो प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक शिक्षा को एक सतत प्रक्रिया के रूप में परिकल्पित करती है। इस योजना को एनईपी 2020 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई), निपुण भारत के लिए सहायता, सभी स्तरों पर गुणवत्ता और नवाचार, समानता और समावेश, कौशल शिक्षा, आईसीटी और डिजिटल पहल आदि जैसे नए मध्यवर्तनों को योजना में शामिल

किया गया है। तमिलनाडु राज्य के लाखों छात्र शुरुआत से ही इस योजना के प्रावधानों से लाभान्वित हो रहे हैं। समग्र शिक्षा के तहत तमिलनाडु राज्य को निधियां जारी करने के संबंध में, वर्ष 2023-24 के लिए सभी चार संस्वीकृत किस्तों में 1876.15 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा तमिलनाडु राज्य के लिए 4305.66 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

(ग) से (ड.): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 इस बात पर बल देती है कि जहां तक संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक, लेकिन अधिमानतः कक्षा 8 और उससे आगे तक, शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी। इसलिए, एनईपी 2020 तमिलनाडु के स्कूलों में तमिल पढ़ाने के विचार का पूरी तरह से समर्थन करती है।

इसके अलावा, संघीय सिद्धांतों का सम्मान करते हुए, एनईपी 2020 इस बात की पुष्टि करती है कि संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए त्रि-भाषा फार्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा। तथापि, त्रि-भाषा फार्मूले में अधिक छूट होगी और किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाएँ राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों की पसंद होंगी, बशर्ते कि तीन भाषाओं में से कम से कम दो भारत की मूल भाषाएँ हों। विशेष रूप से, जो छात्र अपनी पढ़ाई की तीन भाषाओं में से एक या अधिक को बदलना चाहते हैं, वे कक्षा 6 या 7 में ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि वे माध्यमिक विद्यालय के अंत तक तीन भाषाओं (साहित्य स्तर पर भारत की एक भाषा सहित) में बुनियादी दक्षता प्रदर्शित करने में सक्षम हों।

******